ब्रहस्पतिवार, 9 अप्रैल, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर वॉर्नर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

दीपिका पादुकोण ने 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता पर उठे सवालों को किया खारिज

Page-05

यह मामला IPC की धारा 294 के तहत अश्लीलता की परिभाषा को लेकर उठा था।कोर्ट के इस फैसले से भविष्य में ऐसे मामलों की कानूनी व्याख्या पर असर पड़ेगा।

गाली-गलौज को 'अश्लीलता' नहीं माना जाएगा, IPC धारा 294 की नई व्याख्या

- **अपशब्दों को तब तक अश्लील नहीं माना जाएगा, जब तक उनमें यौन या कामुक तत्व न हो।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने IPC धारा 294 की सीमाएं स्पष्ट करते हुए सजा को रद्द किया।**

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि गरमागरम बहस के दौरान बोले गए अपशब्द अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत "अश्लीलता" नहीं माने जाएंगे। अदालत ने कहा कि किसी शब्द को अश्लील मानने के लिए उसमें यौन या कामुक तत्व होना अनिवार्य है।न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि "बेशर्म" जैसे शब्द किसी व्यक्ति की कामुक भावनाओं को भड़काने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने माना कि वर्तमान समय में बहस या विवाद के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आम हो चुका है, इसलिए इन्हें केवल इस आधार पर अश्लील नहीं कहा जा सकता।इस मामले में अदालत ने अपीलकर्ताओं की सजा को रद्द करते हुए कहा कि IPC में "अश्लील" शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। हालांकि, धारा 292 का हवाला देते हुए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अश्लीलता वही मानी जाएगी जो किसी व्यक्ति की कामुक रुचि को उत्तेजित करे।कोर्ट ने अपोर्व अरोरा बनाम राज्य मामला का उल्लेख करते हुए दोहराया कि अश्लीलता का संबंध यौन उत्तेजना से होता है, न कि केवल आपत्तिजनक या असभ्य भाषा से। अदालत ने यह भी कहा कि भले ही अपशब्दों का प्रयोग अनुचित और असभ्य हो सकता है, लेकिन इसे कानून के तहत "अश्लीलता" की श्रेणी में रखना सही नहीं होगा।इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपराधिक कानून की व्याख्या के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

भारत के परमाणु प्रोग्राम में बड़ी छलांग!

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है, जिससे पड़ोसी पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है। तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने सफलतापूर्वक "क्रिटिकैलिटी" हासिल कर ली है।क्रिटिकैलिटी वह अवस्था होती है, जब परमाणु रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थिर होकर बिना बाहरी मदद के लगातार चलती रहती है। यह किसी भी परमाणु रिएक्टर के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस उपलब्धि के बाद पाकिस्तान के आर्म्स कंट्रोल एडवाइजर जाहिर काजमी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि भारत का यह कार्यक्रम उसकी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को तेजी से बढ़ा सकता है।काजमी ने दावा किया कि भारत का PFBR भविष्य में बड़े पैमाने पर हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम तैयार कर सकता है, जिससे देश हर साल सैकड़ों परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास पहले से मौजूद अन्य परमाणु परियोजनाएं इस क्षमता को और मजबूत करती हैं। इसके अलावा, उन्होंने अग्नि-V और अग्नि-VI मिसाइलों का जिक्र करते हुए यूरोपीय देशों को भी सतर्क करने की कोशिश की।

कैबिनेट के बड़े फैसले

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, शहरी परिवहन और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि बालोतरा के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की लागत बढ़ाकर लगभग 79,459 करोड़ रुपये कर दी गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त निवेश को भी मंजूरी दी गई है। यह रिफाइनरी पेट्रोल-डीजल के साथ कई पेट्रो-रसायन उत्पाद तैयार करेगी और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश में दो बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कालई-II (1200 मेगावाट) और कमला (1720 मेगावाट) परियोजनाओं पर कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपये का निवेश होगा। इनसे बिजली उत्पादन बढ़ेगा, राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूती मिलेगी और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी गई है। 41 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 36 स्टेशन होंगे और यह शहर के प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा। परियोजना की लागत 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है और इसे 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कश्मीर में 'ईरान की जीत' का जश्न!

युद्धविराम के बाद सड़कों पर उतरे लोग, लहराए झंडे

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की घोषणा के बाद कश्मीर घाटी में कई जगहों पर जश्न का माहौल देखने को मिला। खासकर शिया बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और इस घटनाक्रम को ईरान की "जीत" बताया।श्रीनगर के सैदाकदल और जदीबल क्षेत्रों के अलावा बडगाम, बारामूला, गांदरबल, पुलवामा और बांदीपोरा जिलों में भी लोग इकट्ठा होकर खुशी मनाते नजर आए।लोगों ने ईरानी झंडे लहराए, पटाखे फोड़े और एक-दूसरे को कश्मीरी कहवा बांटकर जश्न मनाया। कई लोगों का कहना था कि यह संघर्षविराम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की बड़ी जीत है।स्थानीय लोगों ने दावा किया कि ईरान ने इस संघर्ष में अमेरिका और इजराइल को झुकने पर मजबूर कर दिया, इसलिए यह जश्न मनाया जा रहा है। वहीं, कुछ कश्मीरी नेताओं ने भी युद्धविराम का स्वागत करते हुए सवाल उठाया कि इस संघर्ष से अमेरिका को आखिर क्या हासिल हुआ।इससे पहले भी घाटी में ईरान के समर्थन में बड़े स्तर पर फंड जुटाने के अभियान चलाए गए थे, जिसमें लोगों ने आर्थिक और अन्य तरह की मदद दी थी।गौरतलब है कि कश्मीर और ईरान के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक जुड़ाव रहा है। इसी कारण कश्मीर को अक्सर 'ईरान-ए-सगीर' यानी

गाजा-ईरान युद्ध के बाद अमेरिका की साख पर असर, अरब दुनिया का झुकाव चीन-रूस की ओर

मध्य पूर्व में जारी संघर्षों ने वैश्विक शक्ति संतुलन को नया रूप देना शुरू कर दिया है। गाजा संकट और हालिया ईरान से जुड़े तनावों के बाद क्षेत्र में अमेरिका की पारंपरिक पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। लंबे समय से इस क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने वाला अमेरिका अब भरोसे के संकट का सामना कर रहा है।अरब देशों में बढ़ती असंतोष की भावना के पीछे हालिया युद्धों के गंभीर मानवीय और आर्थिक प्रभाव हैं। इन संघर्षों के चलते लाखों लोग विस्थापित हुए और हजारों की जान गई। इसके साथ ही, पर्यटन जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्र पर भी गहरा असर पड़ा है। अनुमानों के मुताबिक खाड़ी देशों को पर्यटन राजस्व में 13 से 32 अरब डॉलर तक की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुल आर्थिक नुकसान 200 अरब डॉलर तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।इस बीच, क्षेत्र में चीन और रूस को अधिक संतुलित और भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की नीतियों, खासकर इजराइल के प्रति उसके समर्थन, ने उसकी छवि को प्रभावित किया है।खाड़ी देशों के लिए एक और चिंता का विषय उनके यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, जो हालिया हमलों के दौरान जोखिम का कारण बने। इससे सुरक्षा संबंधी पुरानी धारणाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं।

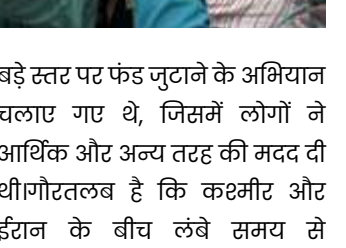

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2 - 3)	फुल पेज (कवर 4 - अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

7.6% से 6.9% पर आई GDP

क्या रफ्तार खो रही है भारतीय इकोनॉमी?

आरबीआई ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष से कम है। पश्चिम एशिया संकट, महंगी जिंस और सप्लाई बाधाएं इसके कारण हैं, जबकि सेवा क्षेत्र, जीएसटी सुधार और मजबूत घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि का रोडमैप जारी करते हुए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमानित 7.6 प्रतिशत से कम है, जो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की रफ्तार में हल्की नरमी के संकेत देता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियों, खासकर पश्चिम एशिया में जारी संकट, का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिंस (कमोडिटी) की ऊंची कीमतें और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे कारक वृद्धि दर को प्रभावित कर सकते हैं। मल्होत्रा ने कहा कि प्रमुख समुद्री मार्गों में बाधा, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव, वैश्विक व्यापार के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके कारण ढुलाई और बीमा लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर भारत के माल निर्यात पर पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन वैश्विक कारकों से घरेलू उत्पादन की गति पर भी दबाव बन सकता है। हालांकि, आरबीआई ने कुछ सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। गवर्नर ने कहा कि सेवा क्षेत्र की मजबूती, जीएसटी दरों के युक्तिकरण, विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग में वृद्धि और वित्तीय संस्थानों तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट घरेलू मांग को सहारा देंगी। इससे अर्थव्यवस्था को आंतरिक स्तर पर स्थिरता मिलने की उम्मीद है। नई जीडीपी श्रृंखला (आधार वर्ष 2022-23) के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके मुकाबले 2026-27 के लिए 6.9 प्रतिशत का अनुमान यह दर्शाता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत सतर्क रुख अपना रहा है। आरबीआई ने तिमाही आधार पर भी वृद्धि के अनुमान जारी किए हैं। इसके अनुसार, पहली तिमाही में वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह संकेत देता है कि साल के उत्तरार्ध में आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुधार हो सकता है। गवर्नर ने यह भी कहा कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता का असर घरेलू वित्तीय परिस्थितियों पर पड़ सकता है, जिससे वृद्धि की संभावनाओं पर दबाव बनेगा। वहीं, केंद्रीय बजट 2026-27 में रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास दीर्घकालिक दृष्टि से सकारात्मक माने जा रहे हैं।समग्र रूप से, आरबीआई का आकलन यह दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बुनियादी कारकों के बावजूद वैश्विक चुनौतियों से अछूती नहीं है। ऐसे में संतुलित नीतिगत कदम और घरेलू मांग की मजबूती ही आने वाले समय में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है।

सीजफायर के पीछे चीन!

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका और ईरान के बीच घोषित दो सप्ताह के संघर्षविराम के पीछे चीन की कूटनीतिक भूमिका को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि बीजिंग ने आधिकारिक रूप से अपनी भूमिका की पुष्टि नहीं की है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों में संकेत दिए गए हैं कि चीन ने पर्दे के पीछे रहकर ईरान को वार्ता के लिए तैयार करने में अहम योगदान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अप्रत्यक्ष रूप से चीन की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि बातचीत शुरू करवाने में चीन की भूमिका रही हो सकती है। इस घटनाक्रम को वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। संघर्ष विराम की घोषणा ट्रंप ने अपनी निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने से महज 90 मिनट पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया। इसके तहत अमेरिका और ईरान दोनों ने दो सप्ताह तक किसी भी सैन्य कार्रवाई से परहेज करने पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित और निर्बाध रूप से खोलने पर सहमति दी है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है। वहीं, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी संघर्षविराम की पुष्टि करते हुए कहा कि वह इस अवधि में अमेरिका के साथ आगे की वार्ता के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के अनुसार, आमने-सामने बातचीत को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका को ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिसे व्यापक समझौते की दिशा में एक आधार माना जा रहा है।

ईरान की रणनीतिक बढ़त!

10 शर्तों के साथ अमेरिका को बातचीत पर मजबूर किया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दो सप्ताह के संघर्षविराम की घोषणा ने वैश्विक राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक हमले टालने का ऐलान करते हुए संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रगति हो रही है। इस घटनाक्रम को कई विश्लेषक ईरान की रणनीतिक बढ़त के रूप में देख रहे हैं।हाल ही में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़े बयान देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन अब उनका रुख नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। दो सप्ताह के सीजफायर के ऐलान के साथ ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस बीच, ईरान की ओर से रखी गई 10 प्रमुख शर्तें चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। ईरान ने सबसे पहले सुरक्षा की गारंटी और स्थायी शांति की मांग रखी है, जिसमें लेबनान जैसे क्षेत्रों में भी संघर्ष समाप्त करने की बात शामिल है। इसके अलावा, अमेरिका से सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने, सेकेंडरी सैंक्शंस खत्म करने और संयुक्त राष्ट्र व अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी (IAEA) से जुड़े प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग की गई है।ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के तहत यूरेनियम संवर्धन की अनुमति बनाए रखने पर भी जोर दिया है। साथ ही, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए शुल्क निर्धारण की मांग की है। ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे और क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को भी अपनी शर्तों में शामिल किया है।

J&K में आतंक पर बड़ा वार!

LG मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारी किए बर्खास्त

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। यह कार्रवाई 8 अप्रैल, 2026 को संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत की गई, जो सुरक्षा कारणों से बिना विभागीय जांच के बर्खास्तगी की अनुमति देता है। यह कदम सरकारी तंत्र में छिपे आतंकी तत्वों के खिलाफ 'शून्य सहिष्णुता' नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। जांच में सामने आया कि उसने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए इलाके में आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने और गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में भूमिका निभाई। सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी पहचान वर्ष 2011 में एक हवाला नेटवर्क की जांच के दौरान की थी, जो मृत आतंकवादियों के परिवारों तक धन पहुंचाने का काम करता था। बताया गया कि उसी वर्ष एक आतंकी से पूछताछ के दौरान उसका नाम सामने आया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, अक्टूबर 2011 में जमानत पर रिहा होने के बाद उसने कथित तौर पर अपनी गतिविधियां जारी रखीं। लंबे समय तक निगरानी के बाद वर्ष 2022 में उसके खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उसे आतंकी नेटवर्क के लिए बिचौलिए और सहयोगी के रूप में काम करने का आरोपी पाया गया। दूसरा बर्खास्त कर्मचारी ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत था, जिसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था। जांच में पता चला कि वह लश्कर-ए-तैबा से जुड़ा हुआ था और बांदीपोरा क्षेत्र में आतंकवादियों को रसद, ठिकाने और संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराता था।

भारत ने US-ईरान सीजफायर का किया स्वागत,

अब शांति की उम्मीद

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया युद्धविराम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में सकारात्मक कदम उठेगा। विदेश मंत्रालय ने 8 अप्रैल, 2026 को जारी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि क्षेत्र में जारी तनाव को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति ही सबसे प्रभावी मार्ग हैं।विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि मौजूदा संघर्ष को जल्द समाप्त किया जाए और सभी पक्ष तनाव कम करने के प्रयास करें। बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि इस संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क को भी गंभीर रूप से बाधित किया है।भारत ने विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक अहम समुद्री मार्ग है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि युद्धविराम के बाद इस मार्ग से निर्बाध और सुरक्षित समुद्री यातायात बहाल होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार सामान्य स्थिति में लौट सकेगा। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि हमले को दो सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। इस निर्णय को दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्धविराम के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप के अनुसार, यह कदम कूटनीतिक प्रयासों के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान अमेरिका और ईरान दोनों से किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से बचने की उम्मीद की जा रही है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर सहमति जताई है, जो वैश्विक तेल परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है।

संपादक की कलम से

बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा बन चुकी है, जो न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है, बल्कि सामाजिक असंतोष को भी जन्म दे रही है। हर साल लाखों छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। इसका एक प्रमुख कारण शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल की कमी है। कई बार छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है, वह बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती, जिससे उन्हें रोजगार पाने में कठिनाई होती है।इसके अलावा, तकनीकी विकास और ऑटोमेशन के कारण भी कई पारंपरिक नौकरियाँ समाप्त हो रही हैं। कंपनियाँ अब कम कर्मचारियों में अधिक काम करने की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे में युवाओं के लिए नए कौशल सीखना और खुद को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, जहाँ रोजगार के सीमित साधन हैं। किसान परिवारों के युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें स्थायी रोजगार नहीं मिल पाता। इससे आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक समस्याएँ बढ़ रही हैं। सरकार द्वारा स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसे अभियान इस दिशा में सकारात्मक प्रयास हैं। लेकिन इन योजनाओं का प्रभाव तभी व्यापक होगा, जब इन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।इसके साथ ही, कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नई तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली में भी सुधार जरूरी है ताकि वह रोजगारोन्मुखी बन सके। अंततः, बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए निजी क्षेत्र, शिक्षा संस्थानों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा। यदि हम अपनी युवा शक्ति को सही दिशा और अवसर प्रदान कर सकें, तो यही युवा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अन्नामलाई ने राहुल गांधी पर निशाना साधा

कोयंबटूर चुनाव प्रचार में भाग न लेने को बताया गठबंधन का असर

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के. अन्नामलाई ने तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने पार्टी की चुनाव रणनीति, जनसंपर्क और सुरक्षा उपायों पर जोर दिया। अन्नामलाई ने महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता को प्राथमिकता बताया, चुनाव में मजबूत प्रदर्शन का लक्ष्य रखा।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के. अन्नामलाई ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और मीडिया से बातचीत में अपनी चुनावी रणनीतियों की रूपरेखा पेश की। अन्नामलाई ने विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की, जिन्होंने हाल ही में कोयंबटूर में चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया। उन्होंने इसे इंडिया गठबंधन के भीतर एकता की कमी का परिणाम बताया। अन्नामलाई ने यह भी बताया कि पुडुचेरी में राहुल गांधी के हालिया भाषण के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मौजूद नहीं थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दोनों नेताओं की व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई।अन्नामलाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने चुनाव संबंधी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये बातचीत मुख्य रूप से चुनाव प्रचार की योजना, जनसंपर्क अभियान और उम्मीदवारों की स्थिति पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में मजबूत जनसंपर्क और व्यापक प्रचार के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। कांग्रेस पार्टी को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि उन्होंने संसद में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत की है और जोर दिया कि विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कानून और नीति दोनों में बदलाव की पहल कर रही है। अभिनेता रजनीकांत की हालिया टिप्पणियों के संबंध में अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें पूरी संदर्भ जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने रजनीकांत को एक महान अभिनेता और उच्च चरित्र का व्यक्ति बताया। इसके अलावा, टीवीके प्रमुख अभिनेता विजय के चुनाव प्रचार पर उन्होंने कहा कि उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। उन्होंने करूर से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का भी जिक्र किया और कहा कि चुनाव प्रचार की अनुमति देने से पहले सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाना चाहिए। नामांकन पत्रों की जांच को लेकर अन्नामलाई ने अविश्वास जताया और पत्रकारों को सलाह दी कि स्पष्टता के लिए अरवाकुरिची का दौरा किया जाए। उन्होंने पार्टी के लिए पास की व्यवस्था करने की पेशकश की और कहा कि यह कदम प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही उन्होंने एएनआई की आलोचना की और जोर देकर कहा कि उन्होंने राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। अन्नामलाई ने चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी की रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करेगी और जनता की समस्याओं को चुनावी मंच पर प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने मीडिया से संवाद में कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में भाजपा की प्राथमिकता जनता की भलाई और विकास पर केंद्रित रहेगी। संपूर्ण बातचीत में अन्नामलाई ने यह स्पष्ट किया कि पार्टी का लक्ष्य चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करना और अपने संदेश को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा अपनी रणनीतियों और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभाएगी और जनता के विश्वास को और मजबूत करेगी।

गुजरात बयान पर घिरे खरगे, विवाद बढ़ने पर जताया खेद

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुजरात को लेकर दिए गए अपने विवादास्पद बयान पर खेद जताते हुए कहा है कि उनके बयान को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और वे गुजरात के लोगों का हमेशा सम्मान करते रहे हैं। खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केरल में उनके हालिया चुनावी भाषण के कुछ अंशों को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वे इस पर खेद व्यक्त करते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब केरल विधानसभा चुनावों से पहले इस मुद्दे पर सियासी विवाद तेज हो गया है।दरअसल, विवाद उस समय शुरू हुआ जब खरगे ने केरल के इडुक्की में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि केरल के लोग "शिक्षित और चतुर" हैं और उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता, जबकि गुजरात और कुछ अन्य क्षेत्रों के लोग आसानी से गुमराह हो जाते हैं। उनके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे गुजरात की जनता का अपमान बताया। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस टिप्पणी से लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक कुंठा के चलते बार-बार गुजरात को निशाना बनाती है और राज्य के राष्ट्र निर्माण में योगदान को नजरअंदाज करती है। संघवी ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बयान उनके योगदान का भी अपमान है। वहीं, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी खरगे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, वहां से कई प्रमुख राष्ट्रीय नेता आए हैं। उन्होंने इस बयान को दुर्भाग्यिपूर्ण बताते हुए कांग्रेस से जवाब मांगा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है और आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है।

हिमाचल की राजनीति गरमाई!

मुख्यमंत्री ने BJP पर लगाया 'सिर्फ राजनीति' का आरोप

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राज्य के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रदेश की जनता के साथ खड़ा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दक्षिण एशियाई टेबल टेनिस युवा चैंपियनशिप 2026 के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को भुना रही है, जबकि राज्य के वैध अधिकारों की पैरवी करने में विफल रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान हिमाचल प्रदेश का जायज हक है और इस मुद्दे पर केंद्र से सहयोग मिलना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मामले में सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय राजनीति को प्राथमिकता दी। इस दौरान स्थानीय विधायक हरीश जनार्थ भी मौजूद रहे।सुक्खु ने दक्षिण एशियाई टेबल टेनिस युवा चैंपियनशिप के आयोजन का स्वागत करते हुए इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता से विशेष रूप से अंडर-19 वर्ग के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को एशियाई खेलों जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। राज्य की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि उनकी सरकार वित्तीय सुधारों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए सुक्खु ने पंचायत चुनावों के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस विषय का अनावश्यक राजनीतिकरण कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई से पहले सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में सरकार ने निचले सदन और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हिमकेयर योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक आंतरिक ऑडिट में लगभग 110 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का पता चला है। उन्होंने

आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले की सच्चाई जनता के सामने लाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार योजना को बंद करने के बजाय उसमें सुधार और पारदर्शिता लाने पर ध्यान देगी। मुख्यमंत्री के इन बयानों से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले समय में इस पर और तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।

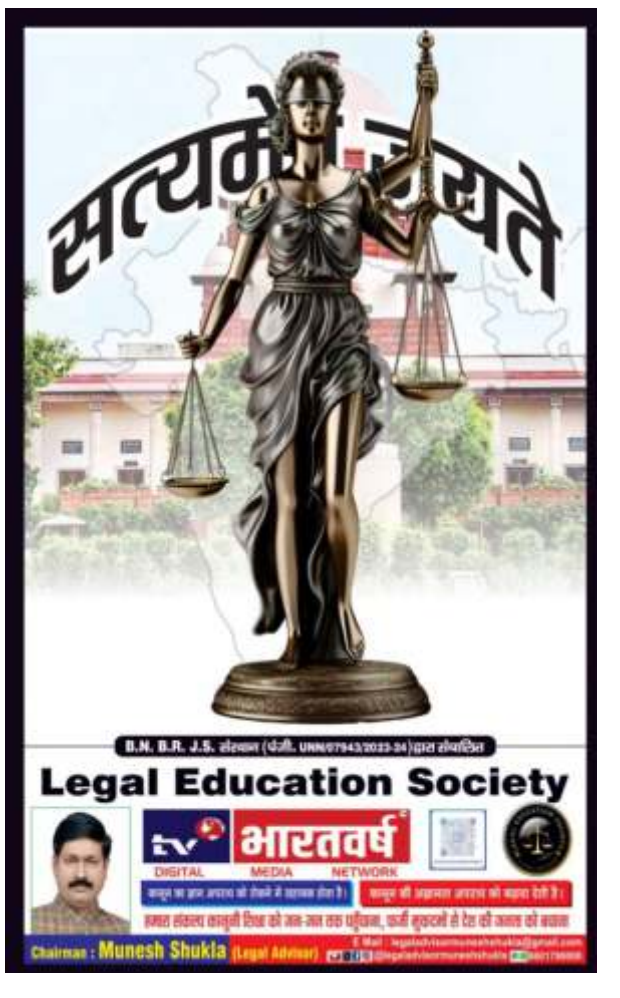

तेल की बड़ी गिरावट के साथ शेयर बाजार में तेजी

रूपया डॉलर के मुकाबले मजबूत

अमेरिका और ईरान के बीच जारी 40 दिन लंबे संघर्ष में दो हफ्ते के सीजफायर की घोषणा ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और वित्तीय बाजारों में राहत की स्थिति पैदा कर दी है। इस खबर के बाद क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) की कीमतों में करीब 15% की बड़ी गिरावट आई, जो लगभग छह साल में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। बुधवार को कच्चा तेल $94.27 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि एक दिन पहले यह $109.27 प्रति बैरल था। यह गिरावट फरवरी की शुरुआत में युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर की तुलना में काफी अधिक है, जब क्रूड ऑयल $73 प्रति बैरल था।विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के दौरान तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब सीजफायर की घोषणा के बाद इस चिंता का अधिकांश हिस्सा समाप्त हो गया है।सीजफायर के समझौते में पाकिस्तान और चीन ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इसके तहत अमेरिका, इजराइल और ईरान ने हमलों को रोकने का संकल्प लिया है। ईरानी सेना की सहायता से होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, जो तेल की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति के लिए अहम मार्ग है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित रूप से न खुला, तो ईरान की सभ्यता को पूरी तरह नुकसान पहुँच सकता है। वैश्विक शेयर बाजारों में इस राहत के संकेत का सकारात्मक असर देखा गया। अमेरिका का S&P 500 फ्यूचर्स 2% बढ़ा, जबकि यूरोपीय बाजारों में 5% की तेजी आई। भारत के शेयर बाजारों पर भी असर पड़ा, सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 4% बढ़ गए। निवेशकों का भरोसा बढ़ने के कारण रूपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, बुधवार के शुरुआती कारोबार में रूपया 41 पैसे मजबूत होकर 92.55 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जबकि मंगलवार को यह 92.96 पर बंद हुआ था।हालांकि, विशेषज्ञ इस राहत को स्थायी नहीं मानते। आईजी के टोनी सिकामोर के अनुसार, यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दे स्पष्ट नहीं हुए हैं। अगर दो हफ्ते के भीतर पूरी तरह से समझौता नहीं होता है, तो कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव सीधे वैश्विक बाजारों, निवेशकों के भरोसे और राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करता है। तेल सस्ता होने से न केवल पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर असर पड़ेगा, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी राहत की खबर है। सीजफायर की अवधि में, तेल की आपूर्ति और कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। यदि दोनों देशों के बीच स्थायी समाधान नहीं निकला, तो कीमतें फिर से तेजी से बढ़ सकती हैं। निवेशक और सरकारें अब वैश्विक तेल बाजार की स्थिति पर अपनी रणनीति बनाएंगी। इस प्रकार, अमेरिका-ईरान संघर्ष में दो हफ्ते के ब्रेक ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और वित्तीय बाजारों में अस्थायी राहत दी है। यह केवल एक शुरुआती सकारात्मक संकेत है और पूरी स्थिति स्पष्ट होने तक तेल की कीमतों और बाजारों में उतार-चढ़ाव बने रह सकते हैं।

लिन शी फेंग को हराकर आयुष ने दिखाया दम, एशियाई चैंपियनशिप में बढ़ाया रोमांच

भारत के बैडमिंटन प्रेमियों के लिए बुधवार का दिन खास रहा, जब आयुष शेट्टी ने एशियाई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन के विश्व रैंकिंग में सातवें नंबर के खिलाड़ी लिन शी फेंग को सीधे गेम में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पिछले साल यूएस ओपन सुपर 300 का खिताब जीत चुके आयुष, जो वर्तमान में विश्व रैंकिंग में 25वें स्थान पर हैं, ने सिर्फ 51 मिनट में 21-13, 21-16 से जीत दर्ज की।मैच की शुरुआत में लिन शी फेंग ने बढ़त बनाई और 4-1 से स्कोर आगे बढ़ाया। लेकिन आयुष ने अपने खेल में सुधार करते हुए स्कोर 7-7 से बराबर कर दिया। इसके बाद उन्होंने शानदार संयम और आक्रामक खेल के जरिए पहला गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में भी चीन के खिलाड़ी ने शुरुआत में 4-1 और फिर 12-9 की बढ़त बनाई, लेकिन आयुष ने लगातार छह अंक बनाकर गेम का रुख बदल दिया और 18-13 तक बढ़त बना ली। अंत में, लिन ने अंतर कम किया लेकिन आयुष ने अपने शानदार खेल और मानसिक दृढ़ता के चलते मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत का कोई भी खिलाड़ी 1965 के बाद पुरुष एकल में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने के करीब पहुंचा है। तब दिनेश खन्ना ने यह कीर्तिमान स्थापित किया था।पुरुष युगल में भारत की ताकतवर जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 2023 में खिताब जीता था। हालांकि, सात्विक की चोट के कारण यह स्टार जोड़ी इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है, जिससे आयुष की जीत और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।आयुष की यह जीत भारत में बैडमिंटन के लिए एक बड़ी प्रेरणा साबित होगी और अगले दौर में उनका खेल और अधिक रोमांचक होने की उम्मीद है।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर वॉर्नर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप

'डिफर्ड मनी' और लेवरेज मॉडल से सुपरस्टार्स कमा रहे अरबों

खेल की दुनिया में एक सच्चाई हमेशा बरकरार रहती है—जो खिलाड़ी जितना मशहूर है, उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती है। आज के दौर में सुपरस्टार एथलीट सिर्फ अपनी टीम के मोहरे नहीं रह गए हैं; वे खुद एक ग्लोबल ब्रांड बन गए हैं। यही कारण है कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज, करियर के ढलान पर होने के बावजूद दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं। इन खिलाड़ियों को पैसे देने का बिजनेस मॉडल भी काफी अलग है। कहीं 'डिफर्ड मनी' (भविष्य में भुगतान) से टैक्स बचाया जा रहा है, तो कहीं 'लेवरेज' का इस्तेमाल कर खिलाड़ी अपनी मांग के मुताबिक राशि वसूल रहे हैं। फुटबॉल में मेसी को अमेरिकन क्लब इंटर मियामी ने सैलरी के साथ हिस्सेदारी भी दी। 38 साल के मेसी को सिर्फ 800 करोड़ रुपए सालाना सैलरी ही नहीं मिली, बल्कि क्लब में इक्विटी और लीग के ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू का हिस्सा भी मिला। वहीं, रोनाल्डो सऊदी अरब के अल-नासर क्लब में सालाना 2000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। सऊदी अरब अपनी छवि सुधारने के लिए रोनाल्डो की स्टार पावर का इस्तेमाल कर रहा है।बेसबॉल में जापानी सुपरस्टार शोहेई ओटानी ने लॉस एंजिलिस डोजर्स के साथ 10 साल के लिए 6450 करोड़ रुपए का करार किया। इसमें से 18.5 करोड़ रुपए सालाना सैलरी के रूप में दिए जाएंगे और बाकी की राशि 2034-2043 तक किश्तों में दी जाएगी। इस 'डिफर्ड मनी' मॉडल से टीम को लग्जरी टैक्स से बचने में मदद मिली। एनएफएल और एनबीए में भी खिलाड़ी अपनी मांग के अनुसार राशि बढ़वाने के विकल्प रखते हैं। एनएफएल में डलास काउबॉयज के डैक प्रेस्कॉट ने सही समय पर टीम पर दबाव डालकर चार साल के लिए 2230 करोड़ रुपए की डील हासिल की। एनबीए में रेवेन्यू खिलाड़ियों और मालिकों में 50-50 बंटता है, और 10 साल से अधिक अनुभव वाले सुपरस्टार्स सैलरी कैप का 35% तक ले सकते हैं।

दीपिका और सविता की वापसी से मजबूत हुई भारतीय महिला हॉकी टीम

भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए आगामी अर्जेंटीना दौरा उत्साह और अनुभव से भरपूर होने वाला है। मंगलवार को मुख्य कोच सलीमा टेटे की अगुवाई में 24 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया, जिसमें ड्रैग-फ्लिक विशेषज्ञ दीपिका और अनुभवी गोलकीपर सविता की वापसी शामिल है। इसके अलावा, डिफेंडर ज्योति और अग्रिम पंक्ति की खिलाड़ी मुमताज खान की भी टीम में वापसी हुई है, जिससे टीम के रक्षण और आक्रमण दोनों विभाग मजबूत होंगे।भारतीय टीम 13 से 17 अप्रैल तक ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के खिलाफ चार मैच खेलेगी। यह दौरा इस साल होने वाले विश्व कप और एशियाई खेलों से पहले टीम के लिए महत्वपूर्ण तैयारी माना जा रहा है। मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने 'हॉकी इंडिया' को दिए बयान में कहा कि यह दौरा टीम संयोजन को परखने और खिलाड़ियों के विकल्प बढ़ाने का अवसर है। उन्होंने बताया कि युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव देने और विभिन्न संयोजनों को आजमाने के लिए यह दौरा बेहद जरूरी है। टीम के लिए सबसे बड़ी मजबूती दीपिका की वापसी है, जो रिहैबिलिटेशन के बाद फिर से टीम की मुख्य ड्रैग-फ्लिकर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उनकी अनुपस्थिति में नवनीत कौर, मनीषा चौहान, उदिता और अनु ने क्वालीफायर मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया था।गोलकीपर सविता की वापसी से अर्जेंटीना के आक्रामक खेल के खिलाफ टीम की रक्षापंक्ति मजबूत होगी। उनकी अनुपस्थिति में विश्व कप क्वालीफायर में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बिछू देवी खारिबाम ने भी टीम में अपनी जगह बनाए रखी है। इस टीम संयोजन के साथ भारत अर्जेंटीना दौरे में अनुभव और संतुलित प्रदर्शन देने की तैयारी में है।

आईसीसी ने क्रिकेट कनाडा को दी चेतावनी, कहा नहीं सुधरे तो यूएस की तरह कड़ा नियंत्रण होगा

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने कनाडा क्रिकेट बोर्ड को सीधी और चेतावनी भरी आगाह जारी की है। आईसीसी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि क्रिकेट कनाडा गंभीर हो और अगर आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो उन्हें यूएस क्रिकेट की तरह कड़ा नियंत्रण झेलना पड़ सकता है। यह चेतावनी अचानक आई है, क्योंकि आमतौर पर आईसीसी की कार्रवाई धीमी होती है। पिछले वर्षों में कनाडा को लंबी छूट दी गई थी, लेकिन अब आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। आईसीसी ने अमेरिका में तेजी से कार्रवाई की थी क्योंकि क्रिकेट ओलंपिक में 2028 में 100 साल के बाद वापस आ रहा है। अमेरिका के पास विशाल मार्केटिंग पावर होने के कारण आईसीसी वहां निवेश और नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहा था। कनाडा के मामले में भी आईसीसी इसी रणनीति के तहत कदम उठा रही है।क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट अमजद बाजवा ने पुष्टि की कि आईसीसी का एक अधिकारी देश में भेजा गया था, जिसने क्रिकेट कनाडा की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शामिल होकर चेतावनी दी। बाजवा ने कहा कि आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर बोर्ड में सुधार नहीं हुआ तो कनाडा क्रिकेट को भी वैसे ही नियंत्रित किया जाएगा जैसे यूएस क्रिकेट पर किया गया।दरअसल, पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मौके आए थे, जब सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आईसीसी ने उन्हें नजरअंदाज किया। पिछले दो वर्षों में मीडिया रिपोर्ट्स ने क्रिकेट कनाडा की कई कमियों को उजागर किया। इनमें सबसे बड़ा मामला सीईओ सलमान खान से जुड़ा था। कैलगरी पुलिस ने उन पर 2014 से 2016 के बीच चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस दौरान कैलगरी एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग से फंड गायब हुए। शुरुआत में खान को सस्पेंड किया गया, बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद नेशनल कोच से जुड़े दो विवाद भी सामने आए। पुबुदु दस्सनायके, जिन्होंने दो साल पहले कनाडा को वर्ल्ड टी20 कप जिताया था और 2027 वर्ल्ड कप में उनकी जगह पक्की थी, को बिना किसी स्पष्ट वजह के हटा दिया गया। उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया है। इसके बाद खुर्रम राशिद चौहान को कोच नियुक्त किया गया, लेकिन उनकी भी चयन प्रक्रिया में विवाद सामने आया। इन घटनाओं के चलते आईसीसी की चेतावनी कनाडा क्रिकेट के लिए गंभीर अलार्म की तरह है। बोर्ड के पास अब

सोशल मीडिया पर अपनी बेफिक्र हंसी के लिए मशहूर तेलंगाना के अरूण कुमार ने इस साल 10वीं की परीक्षा पास कर ली है. कभी ट्रक क्लीनर रहे अरूण को उनके साथी ड्राइवर नेहरू ने न केवल वायरल किया, बल्कि उनकी पढ़ाई पूरी कराकर जीवन बदल दिया.

इंटरनेट की मशहूर मुस्कान वाले लड़के की है दर्दभरी कहानी

चाय का कप और बेफिक्र हंसी

अरूण कुमार है इस वायरल लाफिंग बॉय का नाम (Photo - Social Media)

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कई वायरल मीम या रील के अंत में चाय का गिलास पकड़े और खिलखिलाकर हंसता एक लड़का दिखाई देता है. साधारण से दिखने वाले इस लड़के की हंसी इतनी प्रभावी है कि किसी भी रील, वीडियो या मीम के फन मोमेंट का यह आज सिंबल बन चुका है. इंटरनेट की दुनिया में हंसी और फन का सिंबल बन चुका ये वायरल लाफिंग बॉय कौन है? इस हंसी वाले मोमेंट की क्या कहानी है, जो इतना वायरल हुआ कि आज हर एक रील और मीम में दिखाई देता है. चाय का कप पकड़े, खिलखिलाकर हंसने वाले इस लड़के का नाम अरूण कुमार है. यह तेलंगाना का रहने वाला है. इसकी स्वाभाविक और दिल खोलकर हंसने के अंदाज ने लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई होगी, लेकिन लोगों को हंसाने वाले इस लड़के की खुद की कहानी काफी संघर्ष और मुश्किल भरी है. इन दिनों अरूण इसलिए चर्चा में है, क्योंकि इसने इस साल मार्च में 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास कर ली. जिस शख्स ने कभी इसकी हंसी को कैमरे में कैदकर वायरल किया था. उस नेहरू नाम के व्यक्ति ने ही अरूण को पढ़ा-लिखाकर 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास कराई है. गरीबी के कारण अरूण ने चौथी क्लास तक पढ़ने के बाद बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था. फिर उसे नेहरू नाम के एक ट्रक ड्राइवर साथ मिला. नेहरू ने अरूण को ट्रक पर क्लीनर की नौकरी दे दी. अरूण की जिंदगी नेहरू के साथ ट्रक पर दूर-दराज की यात्रा करते और हाईवे पर ट्रक के टायरों की धूल झाड़ते कटने लगी. ट्रक पर यहां-वहां जाते टाइम पास के लिए नेहरू रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता था.

एक दिन उसने नेहरू का चाय पीते हुए और किसी बात पर बेफिक्री में खिलखिलाकर हंसते हुए पल का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. अरूण की ये बेफिक्र हंसी लोगों को इतनी पसंद आई कि रातोंरात नेहरू का ये वीडियो वायरल हो गया. फिर क्या था, अरूण इंटरनेट पर वायरल लाफिंग बॉय के नाम से फेमस हो गया. आज अधिकतर फनी रील और मीम्स में अरूण की हंसी वाले कुछ सेकेंड का फुटेज जरूर होता है. ⊙

अजनबी को चलती ट्रेन के आगे धकेला

अमेरिका के सिएटल से एक बेहद डराने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को हिला कर रख दिया है. मामला नॉर्थगेट लाइट रेल स्टेशन का है, जहां 19 मार्च 2026 की शाम करीब 6 बजे एक युवक ने प्लेटफॉर्म पर खड़े अजनबी को आती ट्रेन के सामने धकेलने की कोशिश की. पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में साफ दिखता है कि पीड़ित व्यक्ति प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा होकर अपने फोन में व्यस्त था. ⊙

घायल बेजुबान को पीठ पर लादकर चला शख्स

पहाड़ों जैसा ऊंचा हौसला

दूर पहाड़ों के एक गांव से आया एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इंसानियत की ऐसी झलक देखने को मिल रही है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. यहां एक शख्स एक बेजुबान जानवर के साथ अपने रिश्ते को निभाता नजर आ रहा है.वीडियो में दिखता है कि एक आदमी संकरे और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चढ़ाई कर रहा है. उसकी पीठ पर एक बड़ी टोकरी बंधी हुई है. उसी टोकरी में एक घायल आवारा कुत्ता बैठा है, जो अपने पैर की चोट के कारण चलने में पूरी तरह असमर्थ है. रास्ता इतना मुश्किल था कि वहां किसी भी तरह का वाहन पहुंच ही नहीं सकता था. पत्थरों से भरा रास्ता, टूटी सीढ़ियां और

खड़ी चढ़ाई.हर कदम पर चुनौती थी. लेकिन इस शख्स ने हार नहीं मानी. वह धीरे-धीरे कुत्ते को अपनी पीठ पर लेकर ऊपर चढ़ता रहा. उसके साथ एक और व्यक्ति भी था, जो उसे संभालते हुए रास्ता दिखा रहा था. बताया गया कि यह कुत्ता काफी समय से घायल हालत में वहीं पड़ा था और खुद से कुछ भी करने में असमर्थ था. ⊙

लाल शर्ट वाले युवक ने 'कांटा लगा' स्टेप्स से जीता दिल

पेट्रोल पंप पर युवक का डांस वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पेट्रोल पंप के बीचों-बीच बेफिक्र होकर डांस करता नजर आ रहा है. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें युवक बिना किसी झिझक के अपने मन से डांस करता दिख रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना दिन के समय की है, जब पेट्रोल पंप पर रोज की तरह गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी. लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे और पेट्रोल भरवा रहे थे. तभी अचानक एक युवक, जो लाल शर्ट और साधारण पैंट पहने हुए था, वहां आकर डांस करने लगा.शुरूआत में लोगों को लगा कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उसका डांस काफी तेज हो

पहले भी कई लोग सार्वजनिक जगहों पर अचानक डांस करते हुए नजर आए हैं.

गया. युवक को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास कितने लोग हैं या कौन उसे देख रहा है. वह पूरी तरह अपनी ही दुनिया में खोकर नाच रहा था. उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसे किसी भी बात की चिंता नहीं है. डांस के दौरान युवक ने कई मशहूर गानों पर परफॉर्म किया. कभी वह कांटा लगा गाने पर झूमता नजर आया, तो कभी घुंघरू टूट गए जैसे गानों के स्टेप्स करता दिखा. उसके स्टेप्स में आत्मविश्वास और मस्ती दोनों साफ दिखाई दे रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े मंच पर परफॉर्म कर रहा हो, जबकि वह एक साधारण पेट्रोल पंप पर नाच रहा था. ⊙

दीपिका पादुकोण ने 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता पर उठे सवालों को किया खारिज

एक्ट्रेस ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जवाब दिया, जहाँ यूज़र्स ने उनसे पूछा था कि उन्होंने फ़िल्म की सफलता का सार्वजनिक तौर पर जश्न क्यों नहीं मनाया। उस पेज पर एक पोल भी चलाया गया था जिसमें फ़ैन्स से पूछा गया था कि क्या यह कोई "सोची-समझी अनदेखी" है या वे उनकी चुप्पी का कुछ ज़्यादा ही मतलब निकाल रहे हैं। सीधे तौर पर जवाब देते हुए दीपिका ने लिखा, "मैंने यह फ़िल्म आप सबसे बहुत पहले देख ली थी," और फिर आगे जोड़ा, "अब मज़ाक किसका बन रहा है?" – यह उन लोगों के लिए एक करारा जवाब था जो उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी का कुछ ज़्यादा ही मतलब निकाल रहे थे। अपने पति की फ़िल्म को लेकर हो रही ज़ोरदार चर्चा से दीपिका की गैरमौजूदगी ने फ़ैन्स के बीच बहस छेड़ दी थी, और कई लोगों ने उनके खुले समर्थन की कमी पर सवाल उठाए थे। हालाँकि, उनका हालिया कमेंट इस सोच को चुनौती देता है कि सोशल मीडिया पोस्ट ही किसी के निजी या पेशेवर समर्थन का एकमात्र पैमाना होते हैं। यह पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस ने रणवीर सिंह की फ़िल्म 'धुरंधर' का समर्थन किया है। दिसंबर 2025 में फ़िल्म की रिलीज़ के आस-पास, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक पॉज़िटिव नोट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने इस एक्शन फ़िल्म के पहले भाग की तारीफ़ की थी और दर्शकों को इसे देखने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने डायरेक्टर आदित्य धर के साथ-साथ फ़िल्म की पूरी कास्ट और क्रू को भी बधाई दी थी। अपने जन्मदिन से पहले हुई एक खास मुलाक़ात के दौरान, पादुकोण ने फ़िल्म की ज़बरदस्त सफलता पर गर्व भी ज़ाहिर किया था। एक्ट्रेस ने दर्शकों से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने 'धुरंधर' देखी है। जैसे ही सभी ने एक सुर में ज़ोर से "हाँ" में जवाब दिया, उनके चेहरे पर खुशी साफ़ झलक रही थी। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फ़िल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' हाल के सालों की सबसे बड़ी हिंदी हिट फ़िल्मों में से एक बनकर उभरी है। फ़िल्म ने हाल ही में भारत में 1,000 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन पार कर लिया है, और सिनेमाघरों में अपनी ज़ोरदार दौड़ जारी रखते हुए इंडस्ट्री के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 20वें दिन, इस फ़िल्म ने SS राजामौली की 'बाहुबली: द कंक्लूजन' को पीछे छोड़ते हुए, नेट कलेक्शन के मामले में अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म का मुकाम हासिल कर लिया। अपनी भव्यता और बॉक्स ऑफ़िस पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर, 'धुरंधर: द रिवेंज' फ़िल्म 'पुष्पा 2' और 'दंगल' जैसी फ़िल्मों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स को लगातार चुनौती दे रही है, और भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कमर्शियल सफलताओं में अपनी जगह और भी मज़बूत कर रही है।

पेड़ों की कटाई पर ब्रेक

चार लेन प्रोजेक्ट खारिज, 7 करोड़ का बजट सरेंडर

लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में समाधान दिवस पर अली नगर खुर्द के ग्रामीणों ने ओमेक्स सिटी पर जमीन कब्जे के आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मुआवजा, रास्ते और सुरक्षा की मांग उठाई। एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया, जबकि अन्य गांवों से भी अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आईं।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में प्रस्तावित कुकरैल नाइट सफारी को जोड़ने वाली सड़क परियोजना में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां इस मार्ग को चार लेन बनाने की योजना थी, अब उसे घटाकर दो लेन करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से 700 से अधिक पेड़ों की कटान टल जाएगी, जिसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 17 फरवरी 2025 को कुकरैल नाइट सफारी तक चार लेन सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी किया था। इस परियोजना का उद्देश्य बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना था। हालांकि, केंद्रीय सशक्त समिति (सीईसी) ने अपनी रिपोर्ट में इस योजना पर गंभीर आपत्तियां जताईं। समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि चार लेन सड़क निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी, जिससे क्षेत्र के पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। सीईसी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने चार लेन सड़क के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके स्थान पर अब पीडब्ल्यूडी को दो लेन सड़क का नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चार लेन परियोजना के लिए स्वीकृत लगभग 7 करोड़ रुपये का बजट भी शासन को सरेंडर कर दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार इस मामले में पर्यावरणीय चिंताओं को प्राथमिकता दे रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी है कि कुकरैल नाइट सफारी के शुरू होने के बाद क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों में काफी वृद्धि होगी। इससे न केवल शोर-शराबा बढ़ेगा, बल्कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अत्यधिक हस्तक्षेप से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है, जो दीर्घकालिक रूप से जैव विविधता के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।दो लेन सड़क के निर्माण से जहां एक ओर यातायात की जरूरतों को संतुलित तरीके से पूरा किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। यह फैसला विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब पीडब्ल्यूडी द्वारा जल्द ही दो लेन सड़क का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद आगे की स्वीकृतियों के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल, इस निर्णय से पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों में राहत की भावना देखी जा रही है, क्योंकि इससे हरित क्षेत्र को बचाने में मदद मिलेगी।

बीकेटी में गेहूं की फसल बर्बाद, किसानों पर दोहरी मार

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को तेज गर्मी से राहत दे दी। आंधी के बाद करीब 12 घंटे से अधिक समय तक हुई रिमझिम बारिश के चलते बुधवार सुबह तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की कमी आई और यह घटकर करीब 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जिससे मौसम सुहावना हो गया।खराब मौसम का असर सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुईं। तेज हवाओं और बारिश के चलते लखनऊ एयरपोर्ट पर चार फ्लाइटों के संचालन पर असर पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौसम का असर देखने को मिला। बीकेटी इलाके में सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल बारिश और आंधी की वजह से प्रभावित हुई, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा।मौसम विभाग के अनुसार, दिन में धूप निकलने पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हालांकि, विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक आंधी और बारिश का असर बने रहने की चेतावनी दी है, जिससे मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

लखनऊ में निजी स्कूल की मनमानी

फीस 25% बढ़ोतरी पर पेरेंट्स का हंगामा

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र में स्थित श्री राम ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल एक बार फिर अभिभावकों के विरोध के चलते चर्चा में आ गया है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले स्कूल प्रशासन पर मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने का आरोप लगा है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पेरेंट्स ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया। मामला 8 अप्रैल का है, जब स्कूल द्वारा जारी किए गए नए फीस शेड्यूल को देखकर अभिभावकों में नाराजगी फैल गई। शुरुआत में स्कूल प्रबंधन की ओर से फीस में केवल 6 प्रतिशत वृद्धि की बात कही गई थी, लेकिन जब अभिभावकों ने विस्तार से गणना की, तो उन्हें कुल बढ़ोतरी करीब 25 प्रतिशत तक की नजर आई। इस अप्रत्याशित वृद्धि ने अभिभावकों को आक्रोशित कर दिया और वे स्पष्टीकरण मांगने स्कूल पहुंच गए। प्रदर्शन के दौरान कुछ अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन बच्चों पर घर से लाया गया टिफिन न खाने और कैफेटेरिया से भोजन लेने का दबाव बना रहा है। इस आरोप ने विवाद को और बढ़ा दिया। हालांकि, अभिभावकों के विरोध के बाद स्कूल प्रशासन ने इस निर्देश को वापस लेने का फैसला किया। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब बड़ी संख्या में पेरेंट्स स्कूल परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी करने लगे। माहौल बिगड़ता देख स्कूल प्रशासन बैकफुट पर आ गया। मौके पर पहुंचीं स्कूल की प्रिंसिपल शम्मी सिंह ने अभिभावकों से बातचीत कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने पेरेंट्स को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों को

गंभीरता से लिया जाएगा। प्रिंसिपल ने स्कूल मैनेजमेंट से चर्चा के बाद अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बढ़ी हुई फीस पर पुनर्विचार किया जाएगा और इसमें उचित कमी लाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय मांगा। इस आश्वासन के बाद अभिभावकों का गुस्सा कुछ शांत हुआ और उन्होंने फिलहाल अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया।फिलहाल सभी की नजरें स्कूल प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि निर्धारित समय के भीतर फीस में राहत नहीं दी गई, तो अभिभावकों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। यह मामला एक बार फिर निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेकर उठ रहे सवालों को उजागर करता है।

लखनऊ में हाथ-पैर बांधकर 13 साल की लड़की से रेप

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में 13 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। लड़की मंगलवार रात निर्माणाधीन मकान में बेसुध मिली। उसके हाथ-पैर बंधे थे। भाई के मुताबिक, काम करके लौट रही बहन आंधी-बारिश से बचने के लिए निर्माणाधीन मकान में रुकी थी। इसी दौरान 17 साल के नाबालिग आरोपी ने चार दोस्तों के साथ उसे बंधक बना लिया। बहन के साथ मारपीट की और रेप किया। भाई के मुताबिक, बहन घर नहीं पहुंची तो हम लोग खोजते हुए मौके पर पहुंचे। हमें देखकर आरोपी भागने लगे। दो आरोपी छत से कूद गए, जिससे उन्हें चोट आई। शोर सुनकर आसपास के लोग जुट गए। पांचों आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है- पूछताछ में लड़की ने बताया है कि आरोपी उसका परिचित है। उसी ने उसके साथ रेप किया है। दोस्तों ने उसका साथ दिया। बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मामला आशियाना थाना क्षेत्र का है। नाबालिग लड़की मूल रूप से कन्नौज की रहने वाली है। परिवार के साथ आशियाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। पिता राजमिस्त्री हैं। मां घरों में काम करती हैं। भाई के मुताबिक, मां की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके चलते मंगलवार शाम को बहन मां की जगह घरों में काम करने गई थी।

लखनऊ में अवैध प्लाटिंग तोड़ने पहुंचे अफसरों का घेराव

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र के बिकामऊ गांव में मंगलवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। परिवर्तन जोन-4 की टीम अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण के लिए मौके पर पहुंची थी, जहां पहले से चिन्हित निर्माणों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। एलडीए की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से दो अवैध प्लाटिंग में तोड़फोड़ की। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए और विरोध करने लगे। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और आक्रोशित लोगों ने रिंग रोड स्थित चौराहे पर पहुंचकर एलडीए टीम का घेराव कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कार्रवाई को रोकने की मांग की। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हालांकि, प्रशासन की सख्ती और समझाइश के बाद स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रित की गई और कार्रवाई पूरी की गईएलडीए के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि संबंधित लोगों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही प्लाटिंग और निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में सुरेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, केपी सिंह, आशीष सिंह, राम प्रकाश सिंह और कमला समेत कई लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। अधिकारियों के अनुसार, शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के निर्माण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

UPPCL के निविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल

11 मांगों को लेकर सड़क पर उतरे

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के निविदा कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) के मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की शुरुआत 'इतनी शक्ति हमें देना दाता' प्रार्थना के साथ की, जिसके बाद वे सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर विभाग और अधिकारियों को अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने कई बार ज्ञापन सौंपे और वार्ता के प्रयास भी किए, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इससे उनके बीच नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है।निविदा कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें बेहद कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है और उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलतीं। उनका कहना है कि वे समान कार्य करने के बावजूद वेतन और सुविधाओं के मामले में भेदभाव का सामना कर रहे हैं। इससे उनके सामने आर्थिक और सामाजिक संकट गहराता जा रहा है।कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों में वेतन वृद्धि, सेवा सुरक्षा, स्थायीकरण

और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग प्रमुख रूप से उठाई है। उनका कहना है कि अगर समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया, तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बिजली कार्य बाधित करने जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दोहराया कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं और जब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन के चलते क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ और पुलिस प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए मौके पर तैनात रहना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि वह कर्मचारियों की मांगों को लेकर क्या कदम उठाता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत शक्ति संवाद

छात्राओं में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में प्रदेश सरकार के विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 (चरण-द्वितीय) के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में "हक की बात जिलाधिकारी के साथ" मेगा इवेंट और "शक्ति संवाद" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनमें आत्मविश्वास विकसित करना और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुला संवाद स्थापित करना रहा। महिला कल्याण विभाग द्वारा 19 मार्च से संचालित 30 दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों की लगभग 70 हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को अपने विचार और सवाल सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिला। छात्राओं ने शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं, खेलकूद के अवसर, कैरियर मार्गदर्शन और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा की।मुख्य विकास अधिकारी एवं प्रभारी जिलाधिकारी कृतिराज ने छात्राओं की जिज्ञासाओं को गंभीरता से सुना और उनका समाधान करते हुए उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज की बालिकाएं देश का भविष्य हैं और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे अपने अधिकारों को समझें, अपने लक्ष्यों को तय करें और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करें।कार्यक्रम के दौरान "शक्ति संवाद" के माध्यम से छात्राओं और अधिकारियों के बीच संवाद का एक सकारात्मक माहौल बना, जिससे छात्राओं में आत्मविश्वास और जागरूकता दोनों का विकास हुआ। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर वे अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इस अवसर पर एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) और जिला विकास अधिकारी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं का योगदान समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और उनके कार्यों को सम्मान देना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी एवं प्रभारी जिलाधिकारी कृतिराज, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जिला विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी (न्यायिक) पुरवा शालिनी तोमर, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमानाथ राय, नगर क्षेत्राधिकारी सफीपुर सोनम सिंह और नगर क्षेत्राधिकारी (लाइन) बिन्नी सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा 40 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, सुपरवाइजरों, हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन और जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिसने बालिकाओं को न केवल जागरूक किया बल्कि उन्हें अपने अधिकारों और संभावनाओं के प्रति सजग भी बनाया।

उन्नाव में अग्निसचेतकों को खास ट्रेनिंग

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में आगजनी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अग्निसचेतकों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए अग्निसचेतकों ने भाग लिया और आग से बचाव तथा राहत कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। शिविर का आयोजन स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ अधिकारियों ने प्रतिभागियों को आग लगने के कारणों, उससे होने वाले नुकसान और बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश आगजनी की घटनाएं लापरवाही के कारण होती हैं, जिन्हें थोड़ी सतर्कता बरतकर रोका जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान अग्निसचेतकों को विभिन्न प्रकार की आग—जैसे विद्युत आग, रसोई गैस से लगने वाली आग और ज्वलनशील पदार्थों से उत्पन्न आग—के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही यह भी सिखाया गया कि अलग-अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस तरह के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। विशेषज्ञों ने फायर एक्सटिंग्विशर के सही इस्तेमाल का प्रैक्टिकल डेमो भी दिया, जिससे प्रतिभागियों को वास्तविक स्थिति में कार्य करने का अनुभव मिल सके।कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि आग लगने की स्थिति में सबसे पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्नाव अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा!

नकली दस्तावेजों पर बनी स्टाफ नर्स

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के जिला महिला चिकित्सालय में कार्यरत एक आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्स पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने का गंभीर मामला सामने आया है। अस्पताल के कार्यवाहक सीएमएस डॉ. अरविंद कुमार आनंद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया और मामले की जांच की मांग उठाई।डॉ. आनंद के अनुसार, यह मामला पिछले लगभग डेढ़ महीने से संज्ञान में था। उन्होंने 23 मार्च को संबंधित स्टाफ नर्स सपना अग्रवाल के जीएनएम प्रमाणपत्र और मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण की सत्यता की जांच के लिए दस्तावेज भेजे थे। 25 मार्च को मेडिकल काउंसिल से प्राप्त जवाब में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र फर्जी हैं और जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख किया गया है, वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। सीएमएस ने बताया कि सपना अग्रवाल की नियुक्ति वर्ष 2020 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय के माध्यम से एक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा की गई थी। शुरुआत में वह ए-स्क्वायर एजेंसी के तहत कार्यरत थीं, जो बाद में आशीष एंटरप्राइजेज में विलय हो गई। उन्हें प्रतिमाह करीब 23 से 24 हजार रुपये वेतन दिया जा रहा था और वह पिछले साढ़े पांच वर्षों से अस्पताल में कार्यरत थीं।डॉ. आनंद ने आरोप लगाया कि जब फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आया, तो संबंधित कर्मचारी ने उन पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगा दिया, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने फिलहाल संबंधित नर्स की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।इस पूरे मामले को लेकर डॉ. आनंद ने लखनऊ स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव, महानिदेशक, अपर निदेशक और मिशन निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर विस्तृत जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्ति और दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी सीएमओ स्तर की होती है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। फिलहाल, इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आजाद अधिकार सेना का हल्ला बोल, पूर्व IPS के लिए Z+ सुरक्षा की मांग

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में आजाद अधिकार सेना ने बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ठाकुर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई।कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के मंडल अध्यक्ष (लखनऊ) और उन्नाव जिला अध्यक्ष हेमंत सिंह सेंगर ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर लंबे समय से भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधियों, सत्ता के दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को उठाते रहे हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है।पदाधिकारियों ने यह भी दावा किया कि ठाकुर के खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो उन्हें दबाने की कोशिश का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि कारावास के दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा। इसके अलावा, लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे उनके जीवन को खतरा बना हुआ है।ज्ञापन में संगठन ने राष्ट्रपति से मांग की है कि अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध दर्ज सभी कथित फर्जी मुकदमों की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषमुक्त पाए जाने पर उन्हें निरस्त किया जाए। साथ ही, राजनीतिक उत्पीड़न पर रोक लगाते हुए उन्हें पूर्ण संरक्षण देने और उच्च श्रेणी की सुरक्षा, जैसे Z या Z+ श्रेणी, प्रदान करने की भी मांग की गई है।संगठन ने माफिया और अराजक तत्वों द्वारा दी गई धमकियों की स्वतंत्र जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। इसके अतिरिक्त, जेल में हुए कथित उत्पीड़न और स्वास्थ्य नुकसान की जांच कर उचित मुआवजा दिए जाने की अपील की गई। कार्यक्रम के समापन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर डॉ. वंदना सिंह (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ), जिला उपाध्यक्ष मुकेश यादव, जिला सचिव कृष्णा शर्मा सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उन्नाव में जीवन बचाने की ट्रेनिंग, डॉक्टरों ने सिखाया CPR का महत्व

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) और बीएलएस (बेसिक लाइफ सपोर्ट) का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कानपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने भाग लिया और हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति में तुरंत किए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी।प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक के मामलों में शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि समय रहते सही तरीके से सीपीआर दिया जाए, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग घबराहट में सही निर्णय नहीं ले पाते, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है।डॉक्टरों ने सीपीआर की पूरी प्रक्रिया को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि जब किसी व्यक्ति की सांस या दिल की धड़कन रुक जाए, तो तुरंत उसे जमीन पर सीधा लिटाकर छाती के बीचों-बीच तेज और नियमित दबाव देना चाहिए। इसके साथ ही मुंह से मुंह में सांस देने की प्रक्रिया भी समझाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि सीपीआर देते समय गति और दबाव का सही संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। बीएलएस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को यह सिखाया गया कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस बुलाने के साथ-साथ मरीज की स्थिति को कैसे स्थिर रखा जाए। डॉक्टरों ने बताया कि गोल्डन टाइम यानी पहले 5 से 10 मिनट में यदि सही कदम उठाए जाएं, तो मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

उन्नाव रेलवे साइट पर मजदूरों का दर्द, 'ऐसा खाना कि जानवर भी न खाएं'

उन्नाव में पुराने रेलवे गंगापुल पर चल रहे एच-बीम स्लीपर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने भोजन और रहने की व्यवस्था को लेकर गंभीर शिकायतें की हैं। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें बेहद खराब गुणवत्ता का खाना दिया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक मजदूर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ग्रुप-डी स्तर के कर्मचारियों को सुबह का नाश्ता तक उपलब्ध नहीं कराया जाता और कई बार चाय भी नहीं मिलती। ऐसे में उन्हें खाली पेट काम करना पड़ता है। वहीं, दोपहर और रात में मिलने वाला भोजन भी बेहद निम्न स्तर का होता है। मजदूरों के अनुसार सब्जी में स्वाद नहीं होता, उसमें पानी अधिक होता है और पूड़ी व खिचड़ी भी सही तरीके से नहीं बनाई जाती। श्रमिकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसा भोजन दिया जा रहा है जिसे खाना मुश्किल है, जिसके कारण कई लोग मजबूरी में घर से खाना लाने लगे हैं। उनका यह भी आरोप है कि जहां मजदूरों को खराब भोजन दिया जा रहा है, वहीं अधिकारियों के लिए अलग से बेहतर भोजन की व्यवस्था की जाती है। रहने की व्यवस्था को लेकर भी मजदूरों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मच्छरों की अधिकता के कारण रात में सोना मुश्किल हो जाता है और न तो मच्छरदानी उपलब्ध है, न ही साफ-सफाई का समुचित प्रबंध। मजदूरों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने नहीं आया। उन्होंने रेलवे प्रशासन से भोजन की गुणवत्ता सुधारने और रहने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना किसानों की मुसीबत
सीएम ने बताई वजह

लखनऊ में कृषि विज्ञान कांग्रेस-2026 के शुभारंभ पर सीएम योगी ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मौसम बदलाव का कारण बताया। उन्होंने देसी कृषि पद्धतियों पर जोर दिया और किसानों के हित में सरकारी प्रयास गिनाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस-2026 का शुभारंभ किया और इस अवसर पर कृषि, मौसम और किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से बातचीत का एक रोचक किस्सा साझा करते हुए बताया कि हाल ही में उन्होंने कृषि मौसम वैज्ञानिकों से पूछा था कि खेती के समय अचानक मौसम क्यों बिगड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे "वेस्टर्न डिस्टर्बेंस" को मुख्य कारण बताया, जो ईरान और पाकिस्तान क्षेत्र में उठने वाले बवंडरों से प्रभावित होता है और भारत में असमय बारिश व ओलावृष्टि का कारण बनता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की प्राकृतिक चुनौतियां लगातार सामने आती रहेंगी और इनसे निपटने के लिए हमें अपनी पारंपरिक यानी देसी कृषि पद्धतियों को और मजबूत करना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस संदेश का भी उल्लेख किया कि भारत को अपनी जड़ों से जुड़कर खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में 44-45 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और इसका आधार कृषि, किसान और कारीगर थे। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान केवल उत्पादक ही नहीं था, बल्कि कारीगर और उद्यमी भी था। लेकिन आक्रांताओं और औपनिवेशिक शासन ने न केवल कृषि व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, बल्कि यहां की उद्यमिता को भी कमजोर किया। उन्होंने 'वंदे मातरम्' और आनंदमठ का जिक्र करते हुए बताया कि किस प्रकार बंगाल के अकाल और शोषण ने किसानों को कर्ज के बोझ तले दबा दिया था।मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज कृषि और किसान सरकार के एजेंडे में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा देता है। एथेनॉल उत्पादन में भी प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है, जो 41 करोड़ लीटर से बढ़कर करीब पौने दो लाख करोड़ लीटर तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों को लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया है। योगी ने कहा कि राज्य की 122 चीनी मिलों में से अधिकांश अब समय पर भुगतान कर रही हैं और कई मिलें 6-7 दिन के भीतर ही गन्ना मूल्य का भुगतान कर देती हैं। इससे किसानों का विश्वास बढ़ा है और निवेश के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। उन्होंने 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय किसानों और जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास की कमी थी। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था, बिचौलियों का बोलबाला था और सरकारी खरीद केंद्र प्रभावी रूप से काम नहीं करते थे। लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है और किसानों के लिए स्पष्ट नीतियां बनाई गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पिछले 15 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का भी जिक्र किया, जिससे हजारों एकड़ फसलें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने सर्वे कराकर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में 'उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना 2025-26' के तहत 15 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वाले 30 अन्य वैज्ञानिकों को भी सम्मान मिला। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकों पर विचार-विमर्श किया गया तथा मुख्यमंत्री ने कई पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया।

गाजियाबाद में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स सोसायटी में मंगलवार को 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत ने बुधवार को पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। मृतका के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया और शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे इलाके में भारी जाम और हंगामा मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए और पुलिस के समझाने के प्रयास विफल हो गए।घटना की गंभीरता को देखते हुए बुधवार सुबह से युवती के कनावनी स्थित घर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके बावजूद परिजन और स्थानीय लोग शव को सड़क पर ले आए और सीआईएसएफ मार्ग जाम कर दिया। इस दौरान मृतका के पिता सड़क पर ही बेहोश हो गए। हंगामा और बढ़ता देख पुलिस ने शव को जबरन कब्जे में लेकर कनावनी श्मशान घाट पहुंचाया, लेकिन परिजन और आसपास के लोग कार्रवाई के खिलाफ दो घंटे तक विरोध करते रहे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए श्मशान घाट का गेट अंदर से बंद कर दिया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए समझाया जा रहा है और जांच में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें परिवार के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड और सोसायटी के लोगों के बयान दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, चित्रकूट में बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर सरकार की सक्रियता अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगी है। योगी आदित्यनाथ की लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा बैठकों का ही परिणाम है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में तेजी से प्रगति हो रही है। बुधवार को इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में 75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन को सौंपा। यह भूमि आवंटन न केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, बल्कि इसे चित्रकूट डिफेंस नोड के व्यवस्थित और चरणबद्ध विकास की दिशा में एक अहम संस्थागत पहल के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदेश में रक्षा विनिर्माण अवसंरचना को मजबूती मिलेगी और उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। चित्रकूट नोड, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जो लंबे समय से औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा माना जाता रहा है। ऐसे में बीईएल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी को भूमि आवंटित करना इस क्षेत्र के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि डिफेंस कॉरिडोर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस परियोजना के जरिए उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाया जाए।

हाथरस में पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

हाथरस जिले के सहपऊ क्षेत्र में गंदे नाले में मिले पत्रकार के शव के मामले में जिले के पत्रकारों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक (एसपी) को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर जिले के पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे।ज्ञापन में पत्रकारों ने पुलिस से आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और न्याय सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही उन्होंने आरोपियों के एनकाउंटर की भी मांग की, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से मुलाकात करने के बाद ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एसपी ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को न्याय दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।इसके साथ ही एसपी ने कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक चौकी प्रभारी और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों ने कहा कि वह मामले पर लगातार नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को न्याय मिले। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि इस तरह के अपराधों पर कड़ी कार्रवाई कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।यह घटना स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए गंभीर चुनौती के रूप में उभरकर आई है और जिले में पत्रकारों और नागरिकों के बीच सुरक्षा और न्याय के प्रति गहरी चिंता पैदा कर रही है।